Rs. 5 crores. If it is so, would the Government like to reconsider increasing it in high-tech industries with export potential so that even the FDI can go, at least, up to 49 per cent?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Sir, there was proposal which was part of the Gupta Committee Report—which is being studies, at the moment, by the Group of Ministers—in which there was a suggestion that export oriented and high-tech areas could be considered for increasing it from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores. However, this is still under the consideration of the Group of Minister. No decision has been taken in this regard.

SHRI V.P. DURAISAMY: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I draw the attention of the hon. Minister to my Unstarred Question No. 2161 dated 10th August, 2000, which is, more or less, on the same subject. Here, the Minister had said that 24% lucrative participation is permitted. The Government should assure the small-scale sector that it would not permit more than 24% equity. The items reserved for the small-scale sector should also not be dereserved. Would the Minister assure this on the floor of the House?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: Sir, I have discussed it at great length.

Commercialization of Agriculture

344. SHRI LAJPAT RAI:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to launch any new scheme to encourage cost effective crops in the country for the commercialization of agriculture; and

(b) if so, the details of such schemes and the crops which would be coverd thereunder?

---

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lajpat Rai.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) There is no new scheme specifically to encourage cost effective cultivation of any particular crop. However, all crop related schemes are formulated to bring about cost effective cultivation and increase the income of the fanners.

लाला लाजपत राय: चेयरमैन साहब, पिछले 30-35 साल के अरसे में एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटीज रिलेटिड इंस्टीट्यूशन्स और किसानों की मेहनत के परिणामस्वरूप देश में अनाज बहुत पैदा हो रहा है, हम सफीसिएंट ही नहीं बल्कि सरप्लस हैं। हमारे यहा दो-दो, तीन-तीन साल का अनाज पड़ा हुआ है जो खराब हो रहा है। क्या यह बात सही नहीं है कि हम अनाज ज्यादा पैदा कर रहे हैं। और तिलहन और दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हमने दालें और तिलहन के इम्पोर्ट को बंद करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए ऐसे कुछ एरियाज निर्धारित किए हैं चुने हैं जहां पर हम दालें ज्यादा पैदा कर सकें?

ऐसे एररियाज में जहां पर अभी तक खेती-बाड़ी नहीं होती है वहां पर पानी मयस्सर नहीं होता है तो क्या ऐसे एरियाज को भी डेवलप करने के लिए सरकार ने कोई उपाय किया है और अगर किया है तो कहां-कहां पर किया है?

श्री नितीश कुमार: सभापति महोदय, जहां तक तिलहन और दलहन का सवाल है इसमें हमारा मुल्क स्वावलम्बी नहीं हो पाया है। यह बात सही है कि अभी भी इसकी कमी है और बाहर से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इनका इम्पोर्ट करना पड़ता है। जहां तक सरकारी नीति का सवाल है। एक अरसे से सरकार की नीति रही है कि तिलहन और दलहन को बढ़ावा दिया जाए और उसमें जो कठिनाई है इस कठिनाई को दूर किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए एक टेक्नोलोजी मिशन द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है,'Technology Mission on Oilseeds and Pulses.' और इसके चलते हुए दलहन और तिलहन के उत्पादन में सुधार आया है। लेकिन इस मामले में कठिनाई यह आती है कि ज्यादातर इनकी खेती रेनफेड एरियाज में ही होती है और रेनफेड एरियाज के फारमिंग को डेवलप करने के लिए भी सरकार की कई योजनाएं हैं, इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ताकि वह ज्यादा बेहतर ढंग से वाटर मैनेजमेंट कर सकें, ज्यादा बेहतर फार्मस प्रैक्टिसिज अपना सकें, फार्म मेकेनाइजेशन पर ध्यान दे सकें। इसको ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जाती हैं और हर साल इस बारे में बेहतर नतीजे प्राप्त हो रहे हैं।

लाला लाजपत राय: सभापति महोदय, मंत्री महोदया का जवाब संतोषजनक नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे यहां अनाज की बहुतायत और तिलहन वगैरह की कमी है और

कैश क्राप्स की कमी है? इसको ध्यान में रखते हुए क्या युनिवर्सिटीज और जो इससे रिलेटिड इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनमें विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा देना अरम्भ हुआ है या नहीं और अगर हुआ है तो कहां-कहां पर हुआ है?

श्री नितीश कुमार: सभापति महोदय, इस संबंध में प्रयत्न जारी रहते हुए बेहतर क्वालिटी, वैरायटीज निकाली जाए, हर योजना में रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स में इस पर काम होता रहता है और किसानों के बीच में इसको रिलीज किया जाता है, उनका डिमोंस्ट्रेशन कराया जाता है, उसको लोग अपनाएं इसके लिए इनको सहायता प्रदान की जाती है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन किसान की जो इच्छा होती है उसके अनुसार ही वह उत्पादन करता है। हम जो नई कृषि नीति लाए हैं, उसका यह उद्देश्य है कि हर इलाके में कृषि का विकास हो। जिन इलाकों में विकास हुआ है, उसके अलावा भी जो बाकी इलाके होते हैं, उनमें भी कृषि का विकास हो और हम चार परसेंट से ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर सकें, यह हमारा उद्देश्य है। किसान के मामले में हमारी इच्छा है, सरकार चाहती है कि किसान जो भी उपजाए, बेहतर रिटर्न उसको मिले। आज हम अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो गये हैं। गेहूं और चावल का जहां तक सवाल है, उस मामले में हम आत्म निर्भर हैं लेकिन इसके उत्पादन पर जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, डायवर्सीफिकेशन का जहां तक सवाल है, यह किसान खुद अडॉप्ट करते हैं। जब उन्हें लगेगा कि हमें डायवर्सीफाई करना चाहिए, वे हर क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए डायवर्सीफाई करेंगे। जैसे दलहन और तिलहन के बारे में कहा, जहां स्थिति बेहतर होती है वहां लोग दलहन को छोड़कर या तिलहन को छोड़कर चावल और गेहूं उपजाने लगते हैं। इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है और सरकार चाहती है कि किसान वह चीज़ उपजाए, जिसमें उसको ज्यादा लाभ मिले।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Torture of Sivakasi children

*345. MISS. MABEL REBELLO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that is Sivakasi children were tortured to cite their age as 14 even though they were 10 years old and employers procured fake medical certificates;

(b) whether monitoring mechanisms for ensuring effective rehabilitation of child labours are being properly implemented; and